RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 240
दि. 31.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

'बजट तैयार करने की प्रक्रिया 2047 के विजन से जुड़ी रहे', अर्थशास्त्रियों संग बैठक में बोले पीएम

नई दिल्ली (जीएनएस)।

पीएम मोदी ने बजट 2026-27 से पहले अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की अहम बैठक की। इस दौरान वैश्विक चुनौतियों और देश की आर्थिक वृद्धि पर चर्चा हुई। पढ़िए इस बैठक से जुड़ी खबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले आयोजित इस विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना रहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ किया कि 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब विभिन्न क्षेत्रों में 'मिशन मोड' में सुधार जरूरी है।

नीति आयोग में आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय 'आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तनः विकसित भारत के लिए एजेंडा' था। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि विकसित भारत का संकल्प अब केवल सरकारी नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की एक 'जन-आकांक्षा' बन चुका है। उन्होंने कहा, "देश की नीति-निर्धारण और बजट प्रक्रिया को हमेशा 2047 के विजन से जुड़ा रहना चाहिए। हमें विश्व स्तरीय क्षमताएं विकसित करने और वैश्विक बाजारों के साथ गहरे एकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे।"

बजट पूर्व बैठक में 2025 में हुए आर्थिक सुधारों के असर पर की गई चर्चा

बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों ने वर्ष 2025 के दौरान हुए विभिन्न नीतिगत बदलावों और उनके सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की। गौरतलब है कि साल 2025 में जीएसटी (ऋ्रळ) स्लैब में बदलाव, आयकर अधिनियम 2025 का लागू होना और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई जैसे बड़े सुधार देखे गए हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक कार्यबल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अर्थशास्त्रियों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक सुझाव दिए। घरेलू बचत बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर विमर्श हुआ।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री भी रहीं मौजूद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में हुई इस बैठक को 1 फरवरी, 2026 को पेश होने वाले बजट की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ बीवीआर ब्रमण्यम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मंथन में हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने विशेषज्ञों से अपील की है कि भारत न केवल अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना करे, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। 'विकसित भारत' के रोडमैप के तहत, सरकार का ध्यान अब जटिल अनुपालनों को कम करने और व्यापार सुगमता अगले स्तर पर ले जाने पर केंद्रित है। भारत अपने लोगों के नवाचार के जोश के बल पर वैश्विक ध्यान का केंद्र बनकर उभरा है और आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह बात कही।

लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए एक लेख में प्रधानमंत्री ने 2025 को भारत की सुधार यात्रा का एक ऐतिहासिक वर्ष बताया। पिछले 11 वर्षों में हुई प्रगति पर निर्णायक रूप से आधारित है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में हुए अगली पीढ़ी के सुधारों की सराहना करती है। इन कदमों का मकसद देश की विकास क्षमता को बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, "मैं कई लोगों से कहता रहा हूं कि भारत सुधार के दौर में है। इस सुधार का प्राथमिक इंजन भारत की जनसंख्या, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है।" उन्होंने आगे कहा, '2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया।'

यूपीः योगी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम आवास पर की मैराथन बैठक; दिल्ली रवाना

लखनऊ (जीएनएस)।

योगी कैबिनेट का मंत्रीमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीएम आवास पर लंबी बैठक की।

प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष की तैनाती के बाद अब सरकार और संगठन में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन में बदलाव पर भी चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक करीब एक सवा घंटे से अधिक देर चली बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा पर चर्चा हुई और लगभग कोर कमेटी की सहमति भी बन गई है।

माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही कभी भी विस्तार पर अमल किया जा सकता है। इसके बाद संगठन के पुर्नगठन का काम शुरू होगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूरे दिन लखनऊ में थे और उनका पूरा समय आरक्षित था। देर शाम को उनके आवास पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा संघ से क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार व अन्य संघ के पदाधिकारी पहुंचे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु गुमला में अंतर्राज्यीय जनसंस्कृति समागम समारोह-कार्तिक जतरा में शामिल हुईं

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (30 दिसंबर, 2025) झारखंड के गुमला में अंतर्राज्यीय जनसंस्कृति समागम समारोह – कार्तिक जतरा में भाग लिया और इसे संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म और कर्मभूमि झारखंड की यात्रा उनके लिए तीर्थयात्रा के समान है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सामाजिक न्याय और आदिवासी गौरव के महान प्रतीक के रूप में हम सब के श्रद्धा के स्रोत हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पंखराज साहब कार्तिक ओरांव ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को समृद्ध बनाया तथा अपना जीवन आदिवासी समुदाय और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। कार्तिक ओरांव जी शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें कार्तिक

ओरांव जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज और देश के समग्र विकास के लिए काम करने का संकल्प लेना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र कई महान आदिवासी नायकों की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी संग्रहालयों की स्थापना द्वारा देश के लोगों को उनकी वीरतापूर्ण प्रेरक गाथाओं से परिचित कराने के प्रयास कर रही है। लेकिन, आदिवासी समुदाय की विरासत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्था का भी दायित्व है कि वे इस क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्रों के महान आदिवासी नायकों के योगदान को देश के युवाओं और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाएं।

राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं से युवाओं और भावी पीढ़ियों को जोड़ना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपनी आदिवासी विरासत और पहचान संरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा को गति देने वाले ऐतिहासिक सुधारों से संबंधित लिंक्डइन पोस्ट साझा किया

भारत सुधार एक्सप्रेस में सवार है! : प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वर्ष 2025 में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को रेखांकित किया, जिससे भारत तीव्र विकास और प्रगति के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हुआ है। श्री मोदी ने भारत में सुधार की तीव्र गति को रेखांकित करते हुए कहाः 'भारत सुधार एक्सप्रेस में सवार हो गया है!' 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिले।

केरल में शिवगिरि तीर्थयात्रा के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं की शाश्वत प्रासंगिकता को रेखांकित किया

शिवगिरि केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका हैः उपराष्ट्रपति

विश्व को केरल की महान देन आदि शंकराचार्य और श्री नारायण गुरु हैं : उपराष्‌ ट्रपति

श्री नारायण गुरु ने आस्था, तर्क और सामाजिक सुधार को एक सूत्र में पिरोयाः उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने युवाओं से श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज केरल के वर्कला स्थित शिवगिरि मठ में 93वीं शिवगिरि तीर्थयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिवगिरि को केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि श्री नारायण गुरु द्वारा परिकल्पित एक जीवंत दर्शन और सामाजिक जागृति की यात्रा के रूप में वर्णित किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिवगिरि आध्यात्मिक साधना और सामाजिक उत्तरदायित्व के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण का प्रतीक है, जहां आस्था समाज का उत्थान करती है और तर्क भक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है।

उन्होंने कहा कि शिवगिरि तीर्थयात्रा को केवल एक रस्म के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वच्छता, संगठन, कार्य और आत्मसम्मान के माध्यम से जागृति के एक आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया था।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु द्वारा पूछे गए एक महत्‍वपूर्ण प्रश्न ने समाज को बदल दियाः एक मनुष्य को दूसरे से कमतर क्यों समझा जाना चाहिए? गुरु ने सदियों के इस अन्याय का जवाब उन शब्दों से दिया जिन्होंने भेदभाव को हिलाकर रख दियाः "मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।"

श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि गुरु की क्रांति शांत, करुणामय और अपरिवर्तनीय थी, जो गरिमा, समानता और मानवता में निहित थी।

गुरु की बौद्धिक गहराई पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने तर्क का त्याग किए बिना आस्था को कायम रखा, अंधविश्वास को अस्वीकार किया और विवेकपूर्ण जिज्ञासा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्म और तर्कशीलता का ये समन्वय गुरु को न केवल अपने समय का संत, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक बनाता है।

भारत के सभ्यतागत लोकाचार पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिकता ने हमेशा प्रेम को पूजा के सर्वोच्च रूप में रखा है। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु ने इस दर्शन को कार्य के माध्यम से जिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि समाज की सेवा कर्मकांड से श्रेष्ठ है और साथी मनुष्यों के प्रति प्रेम ही भक्ति का सबसे सच्चा रूप है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि केरल का विश्व को दिया गया महान योगदान आदि शंकराचार्य और श्री नारायण गुरु हैं, जिनके दर्शन मानवता को प्रेरित करते रहे हैं।

यह देखते हुए कि भारत में तीर्थयात्रा पर्यटन नहीं बल्कि परिवर्तन है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिवगिरि इस सभ्यतागत सत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विभिन्न युगों में संतों ने क्षेत्रों और भाषाओं की सीमाओं को लांघते हुए यात्रा की, जिससे आस्थाओं के बीच सामंजस्य पर आधारित भारत की शाश्वत शक्ति और मजबूत हुई।

केंद्र सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि प्रसाद (पीआरएएसएडी) जैसी योजनाओं, वंदे भारत ट्रेनों सहित बेहतर कनेक्टिविटी और आध्यात्मिक परिपथों के विकास के माध्यम से तीर्थयात्रा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और हैवी वेट टॉरपीडो के लिए 4,666 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्रालय ने 30 दिसंबर, 2025 को क्लोज क्वार्टर बैटल (सीक्यूबी) कार्बाइन और हैवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए कुल 4,666 करोड़ रुपये की लागत के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में संपन्न हुए।

क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन

भारतीय सेना और नौसेना के लिए 2,770 करोड़ रुपये के 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और सहायक उपकरणों के अनुबंध पर भारत फोर्ज लिमिटेड और पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए। यह उपलब्धि 'आत्मनिर्भर भारत' की विजन के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विश्व-स्तरीय मारक क्षमता से लैस करने और पुरानी प्रणालियों को अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से बदलने के असाधारण और निरंतर प्रयासों की परिणति है।

आधुनिक पैदल सेना के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन और उच्च मारक क्षमता के कारण निकटवर्ती युद्ध में निर्णायक बढ़त प्रदान करती है, जिससे सीमित स्थानों में भी त्वरित और निर्णायक मारक क्षमता सुनिश्चित होती है। यह अनुबंध सरकार और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल को दर्शाता है, जिससे मेक-इन-इंडिया पहल को और गति मिलेगी। यह परियोजना समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और कंपोनेंट के निर्माण और कच्चे माल की आपूर्ति के माध्यम से भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करके स्वदेशी रक्षा उद्योगों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारी वजन वाले टॉरपीडो

भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों (पी-75) के लिए 48 भारी वजन वाले टॉरपीडो और संबंधित उपकरणों की खरीद और एकीकरण के लिए लगभग 1,896 करोड़ रुपये की लागत से इटली की डब्ल्यूएएसएस सबमरीन सिस्टम्स एस.आर.एल. के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अधिग्रहण से छह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी। टॉरपीडो की डिलीवरी अप्रैल, 2028 से शुरू होगी और 2030 की शुरूआत तक पूरी हो जाएगी।

इन टॉरपीडो में महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताएं और उन्नत तकनीकी विशेषताएं हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन चरित्र पर आधारित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' को मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल सहित मंत्रियों ने रसपूर्वक देखा

अहमदाबाद में 150 कलाकारों द्वारा प्रधानमंत्री के जीवन, विचार और राष्ट्र-निर्माण की यात्रा का प्रेरणादायक प्रस्तुतिकरण

राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रोत्साहक उपस्थिति

गांधीनगर, 30 दिसंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, विचार, कार्य-संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अडिग संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ मंगलवार को आयोजित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' को मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने देखा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सर्वश्री कनुभाई देसाई, जीतुभाई वाघाणी, कुंवरजीभाई बावळिया, नरेशभाई पटेल, अर्जुनभाई मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य भी

सहभागी बने।

अहमदाबाद के घुमा स्थित संस्कार धाम में आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बचपन से लेकर राष्ट्र निर्माण की यात्रा तक के विभिन्न पड़ावों को संगीत, नृत्य, नाट्य और आधुनिक मल्टीमीडिया माध्यम द्वारा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

'नमोत्सव' कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने की भावना को सशक्त बनाने का संदेश सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार श्री साईराम दवे सहित कुल 150 कलाकारों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुति से उपस्थित सभी को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति, सेवा, संकल्प, संस्कार और विकास के मूल्यों को कलात्मक रूप से उजागर किया गया।

संस्कार धाम के अध्यक्ष डॉ. आर. के. शाह ने स्वागत करते हुए सभी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने स्वदेशी अपनाने की शपथ भी ग्रहण की।

इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय मंत्रियों सर्वश्री मनीषाबेन वकील, रमेशभाई कटारा, प्रवीणभाई माली, डॉ. जयरामभाई गामित, कमलेशभाई पटेल, स्वरूपजी ठाकोर, पी. सी. बरंडा, मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ल, पूर्व मंत्रिगण, फिल्म निर्देशक श्री आशुतोष गोवारिकर, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव श्री संजय जाजू, श्री अजयभाई पटेल सहित महानुभावों व बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने रसपूर्वक देखा।

सम्पादकीय

बलात्कार पीड़िता को मिला न्याय

उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी वुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर रेप पीड़िता को न्याय दिया है। यह अत्यन्त दुख और चिता का विषय है कि कानूनी नुक्तो का फायदा उठाकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के दोषी को भी कई बार रियायत दे दी जाती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रादेश के उन्नाव में एक नाबलिक लड़की से बलात्कार के मामले में वर्ष 2019 में पूर्व भाजपा विधायक वुलदीप सिह सेंगर को उम्र वैद की सजा हुई थी। अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के मामले और बच्चे-बच्चियों के यौन शोषण से सुरक्षा के कानून पॉस्को में गंभीर हिसा के प्रावधानों के मुताबिक सजा दी थी। तब यह घटना देश भर में व्यापक चिता और आव्रोश का कारण बनी थी। मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित करने का आदेश दे दिया। इस संदर्भ में एक अहम तथ्य यह है कि दोषी सिद्ध होने के बाद निचली अदालत ने साफ कहा था कि सेंगर को जीवन भर जेल में रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के इस उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा नेता वुलदीप सिह सेंगर की जेल की सजा निलंबित करके उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट के इस पैसले के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर गई और न्याय की दुहाई मांगने पर मजबूर हो गई। पीड़िता के परिवार और अन्य महिला कार्यकताओं ने शुव्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर सेंगर की जमानत के खिलाफ विरोध प्रादर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। जनता के विरोध को देखते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट के पैसले के खिलाफ शुव्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील ने भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालवृष्ण आडवाणी से संबंधित एक मामले में यह अभिनिर्धारण किए जाने का हवाला दिया कि एमपी और एमएलए लोक सेवक होते हैं। मात्र इसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को मिले दिल्ली हाईकोर्ट से राहत को निरस्त कर दिया और यह निाित हो गया कि अब सेंगर को आजीवन जेल में ही रहना होगा। अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने तर्व दिया है कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किए बिना आदेश पारित किया कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सेंगर को अपनी शेष प्रावृतिक जीवन अवधि तक जेल में रहना चाहिए। हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत सजा निलंबन देने में कानून और तथ्यों में गंभीर त्रुटि की है, जबकि इसे गंभीर आपराधिक अतीत और दुष्कर्मो के घृणित अपराधों में उसकी स्थापित संलिप्तता को ध्यान में नहीं रखा गया। दरअसल इस घटना के बाद पीड़िता को जिन हालात का सामना करना पड़ा और उसको जीवन तक पर जिस तरह के जोखिम खड़े हुए थे, वे बेहद अप्रात्याशित हो मगर उससे साफ था कि जघन्य अपराधों के बाद एक ऊंचे राजनीतिक रसूख वाला आरोपी पीड़िता को खामोश करने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस दौरान पीड़िता के पिता की जान चली गई। एक ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी, जिसमें वह परिवार के अन्य लोगों के साथ जा रही थी। उस घटना में पीड़िता और उसका वकील बुरी तरह घायल हो गए, जबकि उसकी दो मौसियों की मौत हो गई। समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में पीड़िता को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। जब किसी रसूख वाले अपराधी की सजा को लेकर रियायत बरतने की खबर आती है, तब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कानून के काम करने के पैमाने क्या हैं? कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को न्याय देने के उद्देश्य से आरोपी की सजा को बहाल कर दिया जो स्वागत योग्य है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने पेयजल सेवाओं का आंकलन करने के लिए जल सेवा आंकलन का शुभारंभ किया

जल सेवा आंकलन गांवों को अपनी जल सेवाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार देता है; ग्रामीण जल प्रशासन के केंद्र में ग्राम जल आपूर्ति समितियां हैं

जन भागीदारी, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी का संगम तब होता है जब जल सेवा आंकलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू होता है

(जीएनएस)। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेवा वितरण और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने आज जल जीवन मिशन (जेजेएम) पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नेतृत्व में संचालित डिजिटल पेयजल सेवा कार्यक्षमता मूल्यांकन उपकरण ' जल सेवा आंकलन' का ई-लॉन्च किया।

यह पहल अवसंरचना निर्माण से सतत सेवा वितरण की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो हर घर जल (एचजीजे) गांवों में पेयजल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थिरता का आंकलन करने के केंद्र में ग्राम पंचायतों और ग्राम संस्थानों को रखती है।

कई ग्राम पंचायतों को हर घर जल का दर्जा प्राप्त होने के साथ, जल जीवन मिशन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां नल कनेक्शन से प्रतिदिन विश्वसनीय और सुरक्षित पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जल सेवा आंकलन को एक सामुदायिक स्वामित्व वाली स्व-मूल्यांकन प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो गांवों को केवल अनियमित और महंगे तृतीय-पक्ष सर्वेक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जल सेवा वितरण प्रणालियों पर सामूहिक रूप से विचार करने में सक्षम बनाती है।

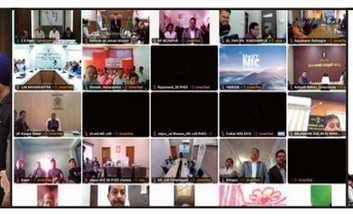

इस टूल का औपचारिक ई-लॉन्च केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने किया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना और श्री राज भूषण चौधरी , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों और संस्थानों के प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, सरपंच और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य उपस्थित थे। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से हर घर जल ग्राम पंचायतों के लगभग 10,000 प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल संसाधन सृजन करना ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सतत आधार पर विश्वसनीय पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने मिशन के चार प्रमुख स्तंभों - राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनभागीदारी, हितधारकों का सहयोग और संसाधनों का इष्टतम उपयोग - का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनभागीदारी हर घर जल की उपलब्धियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है।

उन्होंने कहा कि जल सेवा आंकलन ग्राम पंचायतों को अपनी जल आपूर्ति प्रणालियों का संरक्षक बनने का अधिकार देता है और ग्राम सभाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जनता और गांवों के लिए है, और इसे जारी रखने की जिम्मेदारी स्वयं समुदाय की है; यह केवल जन भागीदारी के माध्यम से ही संभव है।

मंत्री महोदय कहा कि ग्रामीण पेयजल प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता आवश्यक हैं, और यह नया टूल सेवा वितरण में मौजूद कमियों की जल्द पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगा।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और हर घर जल की उपलब्धियों को बनाए रखने और गांवों में बदलाव को गति देने में जन भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जल सेवा आंकलन स्थानीय संस्थानों में सरकार के विश्वास को दशार्ता है और पेयजल सेवाओं के ग्राम-स्तरीय प्रशासन को और मजबूत करेगा।

सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना' पर सिफारिशें जारी कीं

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना' पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

(जीएनएस)। दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने 17.09.2024 के अपने संदर्भ के माध्यम से टीआरएआई से टीआरएआई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत निर्यात उद्देश्यों के लिए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों के आयात/बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और नवीनीकरण के लिए नियम एवं शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था।

इस संबंध में, ट्राई ने 04.07.2025 को 'निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। इसके आलोक में, नौ हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर 25.09.2025 को ऑनलाइन माध्यम से एक खुली बैठक (ओएचडी) आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं आगे के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने 'निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए नियामक संरचना'पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया है।

मशीन-टू-मशीन (एम2एम) संचार एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) एकसाथ मिलकर ऊर्जा ग्रिड, परिवहन प्रणाली, जल आपूर्ति नेटवर्क और कृषि जैसे उद्योगों में अवसंरचना के स्वरुप को आकार दे रहे हैं। एम2एम/आईओटी उपकरणों (जैसे स्मार्ट मीटर, कनेक्टेड कार, औद्योगिक सेंसर) के भारतीय निमार्ताओं को प्रायः विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्ड को अंतःस्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि उपकरण गंतव्य देश में निर्बाध रूप से सेवा प्रदान कर सकें। वर्तमान में, निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री के लिए देश में कोई नियामक संरचना मौजूद नहीं है। नियामक सामंजस्य सुनिश्चित करने एवं निर्यात संचालन को सुचारू बनाने के लिए एक सक्षम नियामक संरचना की आवश्यकता है, साथ ही निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों को शामिल करते समय भारतीय निमार्ताओं को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ध्यान केंद्रीत करना चाहिए।

ट्राई की सिफारिशों के मुख्य बिंदुः

निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक सरल सेवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इस नए सेवा प्राधिकरण को "अंतर्राष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण" कहा जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित स्वतः उत्पन्न प्राधिकरण के साथ ऑनलाइन प्रदान किया जाना चाहिए।

भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण प्राप्त करने का पात्र है। प्राधिकरण के लिए प्रवेश शुल्क, न्यूनतम इक्विटी, न्यूनतम निवल संपत्ति, बैंक गारंटी एवं प्राधिकरण शुल्क शून्य होना चाहिए। प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क 5,000 रुपये है और इसकी वैधता 10 वर्षों के लिए है।

परीक्षण उद्देश्यों के लिए, विदेश के टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों को भारत में अधिकतम छह महीने के लिए सक्रिय करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ट्राई ने सिफारिश की है कि एम2एम/आईओटी क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों एवं आयातकों के लिए बाजार की अपार संभावनाओं को खोलने के उद्देश्य से, दूरसंचार विभाग (डीओटी) को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि) के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि निर्यात के लिए बनाए गए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्ड के आयात और आयात के लिए बने एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ई-सिम कार्डों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्ट नियामक संरचना तैयार की जा सके।

ट्राई की ये सिफारिशें सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करेंगी, जो वैश्विक बाजारों के लिए स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं। ट्राई द्वारा अनुशंसित अंतरराष्ट्रीय एम2एम सिम सेवा प्राधिकरण के लिए नियामक संरचना भारतीय उत्पादों को एम2एम क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर ज्यादा आकर्षक बनाएगा।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

यह सहयोग गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है

राजमार्ग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं मानकों को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन

सुरक्षित एवं ज्यादा टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्गों की दिशा में कदम

(जीएनएस)। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और तृतीय-पक्ष परीक्षण को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

नई दिल्ली स्थित एनएचएआई मुख्यालय में उपभोक्ता मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री भरत खेरा, एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और एनटीएच के महानिदेशक डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ-साथ दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

समझौते के अंतर्गत, एनटीएच को एनएचएआई के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। यह राजमार्ग निर्माण एवं संबंधित कार्यों से जुड़े नमूनों की जांच

एवं निरीक्षण के लिए पूरे देश में स्थित एनटीएच की प्रयोगशालाओं में भेज सकता है। नमूनों की जांच गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलुरु और वाराणसी में स्थित एनटीएच की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं एवं अनुषंगी केंद्रों में की जाएगी। एनटीएच अपने ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल के साथ-साथ भौतिक रिपोर्टों के माध्यम से उचित समय सीमा के अंदर वैज्ञानिक और निष्पक्ष परीक्षण परिणाम प्रदान करेगा।

समझौता ज्ञापन में ऑनलाइन परीक्षण अनुरोध एवं भुगतान, नोडल अधिकारियों के माध्यम से समन्वय और एनएचएआई तकनीकी समितियों में एनटीएच विशेषज्ञों की भागीदारी का प्रावधान भी है। दोनों संगठन मिलकर एनएचएआई अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं क्षमता निर्माण सत्र का आयोजन करेंगे। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, एनटीएच एनएचएआई की प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला की स्थापना 1912 में हुई थी। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख वैज्ञानिक परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन संगठन है जिसकी पहुच पूरे देश में है। इस सहयोग से गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, मानकीकरण एवं दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, स्थायित्व एवं प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद करेगा और इससे भारत सरकार के मजबूत, विश्वसनीय एवं विश्व स्तरीय अवसंरचना के दृष्टिकोण को समर्थन मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय पत्र-मेल सेवाओं का युक्तिकरण

(जीएनएस)। भारतीय डाक विभाग ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के निर्णयों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की दूरदर्शी पहल की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करना, विश्वसनीय, ट्रैकिंग क्षमता, सीमा शुल्क अनुपालन और सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही डाक सेवाओं को विकसित हो रहे वैश्विक ई-कॉमर्स मानकों के अनुरूप बनाना है।

इस अभियान में डाक विभाग ने कुछ अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। इसमें विशेष रूप से वे सेवाएं शामिल हैं जिनमें डाक परिचालन के स्तर पर उनका पता लगाने (ट्रैकिंग) की सुविधा नहीं है या सीमित है। विभाग ने सेवा में अधिक कुशलता, दायित्व और ग्राहक-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है ।

इसी अनुसार, 1 जनवरी 2026 से निम्नलिखित बा' अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्र सेवाएं बंद की जाएंगी :

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के निर्णयों के अनुरूप, पंजीकरण केवल दस्तावेज-आधार पर सीमित किए जाने से पंजीकृत लघु पैकेट सेवा।

बा' देशों में समुद्री या हवाई मार्ग से भेजे जाने वाली छोटे पैकेट सेवा और अन्य सामग्री।

बाहरी डाक वस्तुओं के लिए सरफेस लेटर मेल सर्विस और सरफेस एयर लिफ्टेड (एसएएल) लेटर मेल सर्विस।

यह कदम छोटे पैकेट सेवाओं में सीमित या अनुपलब्ध ट्रैकिंग, डाक सामग्री सुपुर्दगी की लंबी समयसीमा, गंतव्य देशों में बढ़ते सीमा शुल्क और सुरक्षा आवश्यकताओं और कई विदेशी डाक प्रशासनों द्वारा ऐसी वस्तुओं की कम स्वीकृति जैसी चुनौतियों की वजह से उठाया जा रहा है।

डाक विभाग ने स्पष्ट है कि यह युक्तिकरण सेवा गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम है और यह निर्यातकों या ग्राहकों के विकल्पों को सीमित नहीं करेगा। युक्तिकरण के बाद, डाक पंजीकरण केवल हवाई मार्ग से बुक किए गए दस्तावेजी सामग्रियों के लिए ही उपलब्ध होंगे, जो पत्र, पोस्टकार्ड, मुद्रित कागज, एयरोग्राम, ब्लाइंड लिटरेचर और एम-बैग जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिटरेचर और एम-बैग संबंधी मौजूदा यूपीयू प्रावधान बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेंगे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संगठन द्वारा भेजे गए या उन्हें संबोधित दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सामग्री सिवाय लागू हवाई अधिभार के डाक शुल्क से मुक्त रहेंगी। यह गंतव्य देश के नियमों के अधीन संचालित होगा। एम-बैग भार सीमा और देश-विशिष्ट स्वीकृति शर्तो सहित यूपीयू नियमों के अधीन रहेंगे।

निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए डाक विभाग की पहले से ही विदेशों में सामग्री भेजने के सुदृढ़ और विश्वसनीय विकल्प मौजूद हैं। ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा (आईटीपीएस) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सामग्री की पूरी ट्रैकिंग और पारदर्शिता, तेज और अधिक विश्वसनीय डिलीवरी, सीमा शुल्क के बेहतर अनुपालन, सुरक्षा मानकों के पालन और प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी मूल्य संरचना प्रदान करती है।

सभी संबंधित अधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वे इन बदलावों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और ग्राहकों को उपयुक्त वैकल्पिक सेवाओं की जानकारी दें और बदलाव को सुगमता से लागू करने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

सेवाओं का यह युक्तिकरण डाक विभाग की आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित और वैश्विक स्तर पर संरेखित अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता दशार्ता है। इससे अधिक विश्वसनीयता, पारदर्शिता और समग्र ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित होगी।

भारत को वैश्विक स्पेक्ट्रम मानकों के अनुरूप बनाने वाली दूरसंचार विभाग की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (एनएफएपी-2025) 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी

5जी, 5जी एडवांस्ड, भविष्य के 6जी, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और वी2एक्‍स प्रौद्योगिकियों को समर्थन देने के लिए आवंटन का विस्तार

अगली पीढ़ी की सैटेलाइट सेवाओं के लिए आईएमटी और केए/क्‍ यू/वी बैंड के लिए 6425झ 7125 एमएचजेड की नई पहचान

इन-फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएमएमसी) के लिए स्पेक्ट्रम प्रावधानों को बढ़ाया गया

प्रविष्टि तिथिः 30 अ्रउ 2025 12:57ढट्‌ु८ ढक्ह ऊ्र्

देश में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन को नियंत्रित करने वाली संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (एनएफएपी) 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी।

एनएफएपी -2025 के तहत 8.3 किलोहर्ट्ज. से 3000 गीगाहर्ट्ज. की आवृत्ति सीमा में विभिन्न रेडियो संचार सेवाओं के लिए रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा । यह स्पेक्ट्रम प्रबंधकों, वायरलेस ऑपरेटरों और दूरसंचार उपकरण निमार्ताओं के लिए एक आवश्यक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

एनएफएपी-2025 में प्रमुख सुधार

एनएफएपी -2025 अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती स्पेक्ट्रम मांग को पूरा करने के लिए कई रणनीतिक और भविष्य के लिए तैयार संशोधन पेश करता हैः

अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए 6425-7125 मेगाहर्ट्ज बैंड की पहचान , 5जी, 5जी एडवांस्ड और भविष्य के 6जी नेटवर्क के लिए मिड-बैंड स्पेक्ट्रम की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि ।

हाई-थ्रूपुट भू-स्थिर कक्षा (जीएसओ) उपग्रहों और बड़े गैर-जीएसओ उपग्रह तारामंडलों के लिए महत्वपूर्ण, उपग्रह-आधारित सेवाओं के लिए केए, क्‍ यू और वी बैंड का आवंटन।

हवाई और समुद्री परिवहन में निर्बाध ब्रॉडबैंड पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन-फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम।

व्हीकल-टू-एवरीथिंग (वी2एक्‍ स) संचार , एलईओ/एमईओ उपग्रह सेवाओं और विस्तारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी समाधानों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समर्थन।

इन सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि भारत का स्पेक्ट्रम प्रबंधन उत्तरदायी, उच्च क्षमता वाला और वैश्विक मानकों के अनुरूप बना रहे, जो वर्तमान और भविष्य के डिजिटल नवाचारों का समर्थन करेगा और देश में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ाने में मदद करेगा।

पीएम-युवा तृतीय चरण के परिणाम घोषित : 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 43 युवा लेखकों का चयन

(जीएनएस)। शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट-एनबीटी-इंडिया द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना-तृतीय के परिणाम एनबीटी-इंडिया की वेबसाइट पर घोषित कर दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य नवोदित लेखकों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण के अवसर, संपादकीय सहायता और अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप युवा लेखकों को उनके लेखन और विचारों द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

पीएम-युवा तीसरे चरण के तहत, 30 वर्ष से कम आयु के 43 युवा लेखकों का राष्ट्रीय स्तर पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उनके पुस्तक प्रस्तावों के आधार पर चयन किया गया है। इनमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में लेखन प्रस्ताव शामिल हैं। व्यापक स्तर पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में युवा लेखकों का चयन देश में समावेशी साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य को बल देता है। चयननित नवोदित 43 लेखकों में 19 महिलाएं और 24 पुरुष हैं।

इन लेखकों के पुस्तक प्रस्ताव प्रसिद्ध विद्वानों के छह महीने के मार्गदर्शन में पुस्तक के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक चयनित लेखक को 50 हजार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और प्रकाशित पुस्तक पर आजीवन 10 प्रतिशत की रॉयल्टी मिलेगी।

पीएम-युवा तृतीय चरण के विषयों में राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निमार्ता (1950-2025) शामिल रहे। चयनित पुस्तक प्रस्ताव अकाल्पनिक रचनाएं हैं जो इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, दर्शन, शासन, सामाजिक सुधार और भारत की वैश्विक भागीदारी जैसे विषयों द्वारा भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रतिबिंबित करती हैं।

चयनित लेखकों के लिए 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के दौरान राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। पीएम-युवा तृतीय चरण के तहत पुस्तकों का पहला खंड अगले वर्ष प्रकाशित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशों में भारतीय साहित्य और विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए लेखकों की एक नई पीढ़ी का मार्गदर्शन और पोषण करना है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

एक जनवरी, 2026 से वडोदरा मंडल पर ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू

पंचुअलिटी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर आगामी 1 जनवरी, 2026 से नई समय सारणी लागू की जा रही है। ट्रेनों के परिचालन में पंचुअलिटी को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 77 ट्रेनों का समय प्रीपोन किया गया है जिसमें ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक जल्दी आएंगी। इसी तरह 23 ट्रेनों का समय पोस्टपोन किया गया जिसमें ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट से लेकर 40 मिनट बाद आएंगी। वडोदरा मंडल के नडियाद, आनंद, भरूच, अंकलेश्वर, गोधरा, छायापुरी, एकता नगर सहित अन्य स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के आगमन/ प्रस्थान समय में बदलाव होगा, जिसमें ये ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से पहले या बाद में पहुंचेगी। 69172 भरुच – सूरत मेमू 22930 वडोदरा झ दहाणु रोड सुपरफास्ट , 69112 वडोदरा – सूरत मेमू , 69122 गोधरा – वडोदरा मेमू और 69104 आनंद – वडोदरा मेमू को प्रिपोंड कर 5 मिनट पहले किया गया है यानि अब इनका प्रस्थान समय अपने ओरिजनेटिंग स्टेशन से 5 मिनट पहले होगा। यात्रिओं की मांग पर अलीराजपुर – प्रतापनगर मेमू को 15 मिनट पहले किया गया है, अब यह ट्रेन अलीराजपुर स्टेशन से 17.15 बजे की बजाय 17.30 बजे जाएगी।

वडोदरा स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 23 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें वडोदरा स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 से 15 मिनट पहले आयेगी, तथा 7 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें वडोदरा स्टेशन पर वर्तमान समय से 5 से 12 मिनट बाद जायेगी।। एकतानगर स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 2 ट्रेनों यानि ट्रेन संख्या 20950 एकतानगर – अहमदाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 09410 एकतानगर – अहमदाबाद स्टीम हेरिटेज स्पेशल को प्रिपोंड किया गया है तथा 2 ट्रेनों यानि ट्रेन संख्या 20945 एकतानगर – हजरत निजामुद्दीन गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 69206 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू को पोस्टपोंड किया गया है। आनंद स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 18 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें आनंद स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 –7 मिनट पहले आयेगी तथा 4 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें आनंद स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 12 मिनट बाद जायेगी। नाडियाड स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 14 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें नाडियाड स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 –10 मिनट पहले आयेगी तथा 2 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें नाडियाड स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट बाद जायेगी। गोधरा स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 4 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है। भरुच स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 15 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें भरुच स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 –7 मिनट पहले आयेगी। अंकलेश्वर स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 5 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें अंकलेश्वर स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 – 7 मिनट पहले आयेगी। छायापुरी स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 3 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें छायापुरी स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट बाद आयेगी।

रेलवे की यात्रियों से अपील है कि कृपया नई समय सारणी के अनुसार यात्रा करते समय रेल पूछताछ 139, या वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in अवलोकन कर सकते है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच चलाएगी नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

मुंबई, 30 दिसंबर, 2025

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09706/09705 बांद्रा टर्मिनसझ्झजयपुर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल (16 फेरे)

ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनसझ्झजयपुर स्पेशल प्रत्येक सोमवार को 14:40 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08:45 बजे जयपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 05 जनवरी, 2026 से 23 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09705 जयपुरझ्बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक रविवार को 18:40 बजे जयपुर से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 जनवरी, 2026 से 22 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसीझ2 टियर, एसीझ3 टियर, एसीझ3 टियर (इकोनॉमी) एवं स्लीपर क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09706 की बुकिंग 31 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

डीएफएस ने ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारियों की बैठक आयोजित की

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने अधिकरणों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला

बैठक में लोक अदालतों के एडीआर तंत्र के रूप में इष्टतम उपयोग पर चर्चा, डीआरटी में उच्च मूल्य वाले मामलों पर विशेष ध्यान, पीठासीन अधिकारियों, वसूली अधिकारियों, रजिस्ट्रारों और बैंकों के अधिकृत अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। डीएफएस के सचिव ने बैठक में उपस्थित डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

सचिव ने अधिकरणों की प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें अनिवार्य ई–फाइलिंग को अपनाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, हाइब्रिड सुनवाई आदि शामिल हैं। बैठक में अपीलीय अधिकरणों में वसूली प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस चर्चा में शामिल थे:

डीआरटी के माध्यम से वसूली बढ़ाने के लिए बैंकों के सुदृढ़ीकरण, निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र को और मजबूत करने हेतु उपाय;

वसूली को अनुकूलित करने के लिए डीआरटी में उच्च मूल्य वाले मामलों पर विशेष ध्यान देना;

विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का अधिकतम उपयोग;

डीआरटी में निपटान में सुधार के लिए आगे की प्रक्रिया में सुधार;

विभाग और बैंकों द्वारा क्षमता निर्माण के लिए उपायों में पीठासीन अधिकारियों, वसूली अधिकारियों, रजिस्ट्रारों और बैंकों के अधिकृत अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

बैठक में ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन संबंधी सुझावों पर चर्चा की गई, ताकि इन कानूनों की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सके।

अधिकरणों से अन्य डीआरटी में अपनाई जाने वाली ऋण वसूली के मामलों के प्रभावशाली निपटान की सर्वोत्तम विधियों को सीखने का आग्रह किया है।

वर्षांत समीक्षा- 2025 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें नए अभियान और पहल के शुभारंभ के साथ ही अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल

रणनीतिक विस्तारः औद्योगिक विकास को गति देने के लिए संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण सीमाएं लागू हुईं

डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण उपलब्धिः औपचारिककरण में तेजी आने से उद्यम पंजीकरण 7.3 करोड़ से अधिक हुए

ऋण सुलभता में बड़ी सफलताः सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएसई) ने 25 वर्ष पूरे किए; गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई

विरासत का संरक्षण, भविष्य का सशक्तिकरणः पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के 2 वर्षों के भीतर ही 30 लाख लाभार्थी पंजीकरण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया

खादी और ग्राम उद्योग की बिक्री 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुई, जिससे 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को बल मिला

प्रौद्योगिकी–सक्षम शासनः मंत्रालय ने संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए एमएसएमई संपत्तियों को पीएम गति शक्ति के साथ संरेखित किया

प्रविष्टि तिथिः 30 उाउ 2025 12:49ढट ु८ ढक्ह ऊँ

भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कम पूंजी लागत पर पर्याप्त रोजगार सृजित करता है, सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों को सहयोग प्रदान करता है और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है—

क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और आय के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय अपने विभिन्न संगठनों एवं संस्थानों के सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र, जिसमें खादी, ग्राम उद्योग और नारियल उद्योग शामिल हैं, के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रहा है। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों के साथ–साथ ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें नए अभियान और पहल शुरू करना, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। कई नए कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ यह वर्ष मंत्रालय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2025 के दौरान मंत्रालय की कुछ प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

2. वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां और पहलेंः

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का औपचारिककरणः

उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ 01 जुलाई, 2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने और सभी योजनाओं एवं लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क, कागज रहित और डिजिटल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के लाभों का लाभ उठाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पोर्टल का शुभारंभ 11 जनवरी, 2023 को किया।

01 जुलाई, 2020 से 17 दिसंबर, 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर 7.30 करोड़ से अधिक उद्यमों ने पंजीकरण कराया है। इसमें उद्यम पोर्टल पर 4.37 करोड़ और यूएपी पर 2.92 करोड़ पंजीकरण शामिल हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई को परिचालन बढ़ाने और बेहतर संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता के लिए, केंद्रीय बजट 2025–26 में वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। नई परिभाषा 01.04.2025 से प्रभावी हो गई है। तुलनात्मक तालिका नीचे दी गई हैः

रुपये (करोड़ रुपये में) उद्यम, निवेश, कारोबार

पुराना, संशोधित, पुराना, संशोधित

सूक्ष्म, 1, 2.5, 5, 10

लघु, 10, 25, 50, 100 मध्यम, 50, 125, 250, 500

2.2 ऋण तक पहुंचः 2.2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी एक क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये की परियोजना लागत वाले नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लेने वाले लाभार्थियों को मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

21वीं सदी की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएंः भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी के एक नए युग का आगाज कर रही है

इंजीनियरिंग के चमत्कार– चेनाब ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज और बैराबी सैरांग लाइन, यात्रा और आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर के 60 स्टेशनों का विकास कार्य जारी है

..

भारतीय रेलवे 21वीं सदी की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी ढ़ांचागत परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही हैं, रसद व्यवस्था में सुधार कर रही हैं और आधुनिक रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। दुर्गम भूभागों में बने प्रतिष्ठित पुलों से लेकर माल ढुलाई गलियारों और हाई–स्पीड रेल तक, ये परियोजनाएं भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दुनिया को सामने रख रही हैं।

सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल)। यह एक अत्यंत रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार, 272 किलोमीटर लंबी यह रेल पटरी हिमालयी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस परियोजना में चिनाब रेल पुल भी शामिल है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे मेहराबदार पुल है। यह नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है, जो एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। यह 1,315 मीटर लंबा स्टील मेहराबदार पुल है, जिसे भूकंप और हवा की स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस परियोजना में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल–स्टे रेलवे पुल भी शामिल है, जिसे अंजी रेल पुल के नाम से जाना जाता है। परियोजना में 36 सुरंगें (119 किमी लंबी) और 943 पुल शामिल हैं। यूएसबीआरएल कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करता है। यह क्षेत्र में आवागमन, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।

अंजी रेल ब्रिज

तमिलनाडु में बना नया पंबन रेलवे पुल एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह नया पुल भारत का पहला वर्टिकल–लिफ्ट समुद्री पुल है। लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित, 2.08 किलोमीटर लंबा यह पुल 100 स्पैन से बना है, जिसमें 18.3 मीटर के 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक मुख्य स्पैन शामिल है।

पुल में 333 पाइल और 101 पाइल कैप से युक्त एक मजबूत सबस्ट्रक्चर सिस्टम है, जो संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। इसमें कुशल भार वितरण के लिए डिजाइन किए गए 99 एप्रोच गर्डर भी शामिल हैं। इस पुल को चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों और तेज तटीय हवाओं का सामना करने के लिहाज से बनाया गया है। इसकी उम्र बढ़ाने के लिए, एक संक्षारण सुरक्षा प्रणाली प्रदान की गई है, जो बिना रखरखाव के पुल के सेवा जीवन को 38 वर्षों तक और न्यूनतम रखरखाव के साथ 58 वर्षों तक बढ़ा सकती है।

यह नया पुल रामेश्वरम को रेल संपर्क सुनिश्चित करता है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल और पर्यटन केंद्र है। अपने उन्नत डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दशार्ते हुए, नए पंबन रेलवे पुल को पुल डिजाइन श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टील स्ट्रक्चर्स एंड मेटल बिल्डिंग्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।

पंबन रेल ब्रिज

भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई सालों तक इस क्षेत्र को कनेक्टिविटी की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2014 से पूर्वोत्तर में 1,679 किलोमीटर से अधिक रेल पटरी बिछाई गई है। 2,500 किलोमीटर से अधिक मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है। 470 से अधिक सड़क ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। बैराबी–सैरांग नई लाइन पूरी तरह से चालू हो गई है। इससे पहली बार आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। आइजोल अब पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी है, जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर के 60 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। सिवोक–रंगपो, दीमापुर–कोहिमा और जिरीबाम–इम्फाल जैसी प्रमुख परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर के आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को देश के बाकी भागों से जोड़ रही हैं।

बैराबी–सैरांग रेल लाइन का पुल संख्या 144 (कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा)

माल ढुलाई क्षेत्र में, भारतीय रेलवे समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डीएफसी) के जरिए रसद व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। लुधियाना से सोननगर तक फैला पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (ईडीएफसी) 1,337 किलोमीटर लंबा है और पूरी तरह से चालू हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह टर्मिनल को दादरी से जोड़ने वाला पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) 1,506 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 1,404 किलोमीटर यानी 93.2% कार्य पूरा हो चुका है।

दोनों कॉरिडोर मिलकर कुल 2,843 किलोमीटर की लंबाई तय करते हैं। अब तक 2,741 किलोमीटर मार्ग चालू हो चुके हैं, जो कुल लंबाई का लगभग 96.4% है। ये समर्पित कॉरिडोर यात्री मार्गों पर भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर रहे हैं। इनसे यात्रा का समय कम हो रहा है, लॉजिस्टिक्स लागत घट रही है और उद्योगों और बंदरगाहों के लिए विश्वसनीयता बढ़ रही है। ये समर्पित कॉरिडोर भारत में माल ढुलाई को मजबूत कर रहे हैं और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

समर्पित माल ढुलाई गलियारा

भारतीय रेलवे हाई–स्पीड रेल के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। मुंबई–अहमदाबाद हाई–स्पीड रेल परियोजना का कार्यान्वयन एनएचएसआरसीएल द्वारा किया जा रहा है। 21 दिसंबर 2025 तक, कुल 508 किमी की पटरी में से 331 किमी का वायडक्ट कार्य पूरा हो चुका है। 410 किमी के लिए पियर का कार्य पूर्ण हो चुका है। 17 नदी पुल, 5 पीएससी पुल और 11 स्टील पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। लगभग 272 किमी आरसी ट्रैक बेड का निर्माण हो चुका है। 4100 से अधिक ओएचई मास्ट स्थापित किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख सुरंग निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। सूरत और अहमदाबाद में रोलिंग स्टॉक डिपो भी विकसित किए जा रहे हैं।

यह परियोजना भारत में विश्व स्तरीय हाई–स्पीड रेल प्रौद्योगिकी लाएगी। इससे दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत सूरत जिले में बना वायडक्ट

ये ऐतिहासिक परियोजनाएं भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय विकास में भूमिका को दशार्ती हैं। ये बड़े पैमाने पर निवेश और उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं को भी प्रतिबिंबित करती हैं। इन प्रयासों के जरिए भारतीय रेलवे संपर्क में लगातार सुधार कर रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहा है।

आदरज मोटी-विजापुर रेलखंड का सीआरएस पश्चिम सर्कल द्वारा संरक्षा निरीक्षण किया गया

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आदरज मोटीझविजापुर रेलखंड (39.75 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण (सेफ्टी इंस्पेक्शन) रेल संरक्षा आयुक्त (उफ्र), पश्चिम सर्कल द्वारा 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को किया गया।

इस निरीक्षण टीम में श्री ई. श्रीनिवास, रेल सुरक्षा आयुक्त (उफ्र) (पश्चिम सर्कल), श्री वेद प्रकाश, मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण और ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

30 दिसंबर 2025 को आदरज मोटीझविजापुर सेक्शन में नई परिवर्तित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर 120 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इस दौरान लगभग 40 किमी की दूरी मात्र 20 मिनट में तय की गई।

रेल संरक्षा आयुक्त (उफ्र) द्वारा इस परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन को यात्री यातायात के लिए खोलने से पहले ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नलिंग, ब्रिज, ओवरहेड इलेक्ट्रिक (डलए) सिस्टम, सुरक्षा मानकों और ट्रेन की अधिकतम सुरक्षित गति की पूरी तरह से जांच की गई, जिसमें ट्रैक फिटिंग, बैलास्ट, सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग, डलए की ऊंचाई और अन्य सभी सुरक्षा–संबंधी पहलुओं को सुनिश्चित किया गया।

इस रेलखंड में कुल 01 मेजर ब्रिज, 44 माइनर ब्रिज तथा 35 रोड अंडर ब्रिज (फ्वइ) का निर्माण किया गया है तथा इस रेलखंड में आदरज मोटी, रांधेजा, उनावाझवासन, मकाखड़, लोदरा एवं विजापुर स्टेशन शामिल हैं।

आदरज मोटी वर्तमान में एक विद्यमान द्वि–गेज जंक्शन स्टेशन है, जहाँ से आदरज मोटीझगांधीनगरझ अहमदाबाद (ब्रॉड गेज) तथा आदरज मोटीझकड़ीझकटोसन (ब्रॉड गेज) लाइनें जुड़ी हुई हैं। गेज परिवर्तन से पूर्व आदरज मोटीझविजापुर एक पृथक मीटर गेज खंड था, जो अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर एकीकृत रेल नेटवर्क का हिस्सा बन गया है।

इस गेज परिवर्तन परियोजना से आदरज मोटीझविजापुर के बीच एकीकृत ब्रॉड गेज रेल प्रणाली उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा पर्यावरणझअनुकूल, सतत और तेज

व्यापक क्षमता-निर्माण ढांचे के माध्यम से पेशेवर खेल प्रशासन

(जीएनएस)।

खेल विभाग ने भारत को वर्ष 2036 तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में स्थान दिलाने, वैश्विक खेल उत्कृष्टता के लक्ष्य को पूरा करने, खेल प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने और खेल प्रशासकों की क्षमता निर्माण हेतु ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया था।

इस कार्य बल ने हाल ही में खेल विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस व्यापक रिपोर्ट ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी सहित एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, पेशेवर, जवाबदेह और दूरदर्शी खेल प्रशासकों की आवश्यकता पर बल दिया है। कार्य बल ने खेल प्रशासन प्रशिक्षण को विनियमित करने, मान्यता देने और प्रमाणित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय खेल शिक्षा और क्षमता निर्माण परिषद (एनसीएसईसीबी) की स्थापना की सिफारिश की है।

कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में खेल प्रशासकों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक पांच–स्तरीय क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएम) को लागू करने की भी सिफारिश की है। इसका उद्देश्य भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल संघों और राज्य विभागों को कैडर संरचना, पाठ्यक्रम अपनाने, डिजिटल सक्षमता और खिलाड़ी विकास पथों के संदर्भ में संस्थागत परिपक्वता का आकलन करने में सक्षम बनाना है। यह मॉडल साक्ष्य–आधारित निगरानी और लक्षित हस्तक्षेपों को भी समर्थन प्रदान करेगा।

रिपोर्ट में भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के प्रारंभिक और उन्नत प्रशिक्षण में खेल प्रशासन प्रशिक्षण मॉड्यूल को एकीकृत करने की भी सिफारिश की गई है, जिसमें खेल नीतियों के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को मान्यता दी गई है। रिपोर्ट में नियोजित प्लेसमेंट, एक राष्ट्रीय मान्यता रजिस्ट्री और नीति एकीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण को व्यावहारिक अनुप्रयोग और कैरियर की प्रगति से जोड़ने का प्रस्ताव है।

रिपोर्ट में प्रशासकों को पेशेवर रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए रोटेशनल पोस्टिंग, शिक्षुता मॉडल, नवाचार प्रयोगशालाओं और संघों, सरकार और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की भी सिफारिश की गई है।

खेल विभाग वर्तमान में देश के खेल तंत्र को पेशेवर बनाने की दिशा में अपने प्रयासों के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्य बल की सिफारिशों का मूल्यांकन कर रहा है।

खेल विभाग ने खेल प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले ही सुधार शुरू कर दिए हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता योजना के तहत सहायता के मानदंडों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार एनएसएफ अब अपने कुल बजट का 10 प्रतिशत तक प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए आवंटित कर सकते हैं

जिससे उन्हें अधिक प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक पेशेवर कर्मचारी और तकनीकी सहायता मिल सके।

इसके अतिरिक्त, सुचारू प्रशासनिक संचालन, कानूनी सेवाओं और विशेषज्ञ युवा पेशेवरों या प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए आवश्यक व्यय को योजना के तहत वार्षिक बजट के 2.5 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों (एनएसएफ) को उचित प्रशासनिक संरचना रखने और कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए उचित विज्ञापन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

इन सुधारों का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सम्मानित, एथलीट–केंद्रित शासन ढांचे की स्थापना करना है, जिससे भारत को वर्ष 2036 और उसके बाद के खेलों के लिए तैयार किया जा सके। सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 को लागू करके इस तैयारी की शुरूआत कर दी है।

जनसुनवाई:पीलीभीत के एसपी ने सुनी जनशिकायतें, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

(जीएनएस)।

पीलीभीत:जिले में जनशिकायतों के त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ने उपस्थित जनता की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, शहरवासियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें मुख्य रूप से पारिवारिक विवाद, जमीन हड़पने की घटनाएं, चोरी-डकैती जैसे अपराधों की शिकायतें, पुलिस की लापरवाही तथा अन्य प्रशासनिक समस्याएं शामिल रहीं। एसपी ने हर शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए तथा पीड़ितों को न्याय मिले।

इस आयोजन का उद्देश्य आमजनता के बीच पुलिस विभाग के प्रति विश्वास बढ़ाना तथा शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करना है। एसपी ने कहा कि जनसुनवाई को नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। इससे जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी तथा नागरिकों को तत्काल राहत मिल सकेगी। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की तथा आशा व्यक्त की कि निदेशों का कड़ाई से पालन होगा।

अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रदेशवासियों को मिला लाभः ब्रजेश पाठक

वर्ष 2025 में तमाम नई स्वास्थ्य इकाइयों का लोकार्पण एवं नए अस्पतालों का हुआ शिलान्यास

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 दिसंबर वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश की अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का आमजन को भरपूर लाभ मिला। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस वर्ष आधारभूत ढांचे के विस्तार से लेकर अत्याधुनिक इलाज सुविधाओं तक अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इन प्रयासों का सीधा लाभ प्रदेश की करोड़ों जनता को मिला है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनीं। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज (ईसीआरपी)के तहत प्रदेश में चिकित्सा ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती दी गई। वर्ष 2025 में कुल 83 नई स्वास्थ्य इकाइयों का लोकार्पण किया गया तथा एक बड़े अस्पताल का शिलान्यास हुआ। इनमें 26 आईपीएचएल लैब, 38 पचास बेड के फील्ड अस्पताल, 13 जनपदीय ड्रग वेयरहाउस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीसीबी यूनिट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इसके साथ ही सीतापुर में 200 बेड के जिला चिकित्सालय का शिलान्यास भी किया गया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 1800 और जिला अस्पतालों में 1029 आईसीयू बेड स्थापित किए गए। ऑक्सीजन आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (एमजीपीएस) सहित 49 एलएमओ स्टोरेज टैंक स्थापित किए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके तहत 42 बेड वाले पीडियाट्रिक केयर यूनिट जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए गए। वहीं 32 बेड वाले

सभी 23 पीडियाट्रिक यूनिट पूरी से संचालित हुईं। इसके अलावा नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए प्रदेश में 412 न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स (एनबीएसयू) की स्थापना की गई। वर्ष 2024-25 में बा' रोगी सेवाओं में 27 प्रतिशत और अंतः रोगी सेवाओं में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। संस्थागत प्रसव, सिजेरियन डिलीवरी, बड़े और छोटे ऑपरेशन, पैथोलॉजी जांच, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाओं में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ। सभी जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के 74 जनपदों में सीटी स्कैन और सभी 75 जनपदों में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। जनवरी से नवंबर-25 के बीच 9.42 लाख सीटी स्कैन और 6.50 लाख से अधिक डायलिसिस सत्र संचालित किए गए। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल ड्रग लिस्ट का विस्तार किया गया, जिससे प्राथमिक से लेकर जिला अस्पताल स्तर तक दवाओं की संख्या बढ़ाई गई। आयुष्मान भारत मिशन से जुड़े 318 अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 318 अस्पतालों को जोड़ा गया, जिनमें 248 कैंसर उपचार से संबंधित हैं। दिसंबर-25 तक लगभग 3,862 करोड़ रुपये का भुगतान अस्पतालों को किया गया। एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत करते हुए 2,249 नई एंबुलेंस बेड़े में जोड़ी गईं, जिनसे लाखों मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। टीबी उन्मूलन अभियान में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन किया। जांच की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और 7,191 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 424 प्रतिशत अधिक है। ई-संजीवनी सेवाओं के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 75 हजार से अधिक कॉल के साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेली-मानस सेवा सफलतापूर्वक लागू की गई, जिससे लाखों लोगों को परामर्श मिला।

प्राथमिक विद्यालय ज्योरी मे बीते 20 वर्ष शिक्षामित्र के रूप मे सेवा प्रदान

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। प्राथमिक विद्यालय ज्योरी मे बीते 20 वर्ष शिक्षामित्र के रूप मे सेवा प्रदान करने वाले शिक्षामित्र मंशाराम के सेवानिवृत्त होने पर मंगलवार को मसौली चौराहा स्थित पूर्व प्रधान राममूर्ति उर्फ लल्लू यादव के प्रतिष्ठान पर शिक्षा मित्र संघ द्वारा अंगवस्त्र एव साईकिल प्रदान कर विदाई दी गयी।

ए आर पी आदित्य वर्मा एव राजेश यादव ने कहा कि शिक्षण कार्य से जुड़ा व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है बल्कि जीवन भर समाज को सेवा देता है सेवानिवृत्त शिक्षामित्र मंशाराम के सरल व्यक्तित्व और छात्र छात्राओं

के शैक्षणिक विकास मे योगदान की सराहना की। पूर्व प्रधान राममूर्ति यादव ने सेवानिवृत्त शिक्षामित्र के 20 वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि मंशाराम शिक्षण कार्य से भले ही मुक्त हुए है लेकिन समाज को नई दिशा देने मे उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा ।

एडवोकेट रोहित यादव ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षा मित्रों का अहम योगदान है। उनके योगदान की सराहना होनी चाहिए उन्होंने कहा कि शिक्षक की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती है।

इस मौके पर शिक्षामित्र देवेंद्र वर्मा, देवेंद्र यादव, संदीप वर्मा, लवलेश यादव, अमरीश वर्मा, अनीता विश्वकर्मा, नीलू वर्मा, राम कुमार वर्मा, संतोष वर्मा सहित शिक्षामित्र संघ द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षामित्र को भावभीनी विदाई देते हुए साईकिल प्रदान की।

विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति से ही जनपद होगा निपुण : उप शिक्षा निदेशक

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर के ऑडिटोरियम में निपुण भारत मिशन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को लेकर मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप शिक्षा निदेशक एवं डायट प्राचार्य ने अधिकारियों व एआरपी से विस्तृत मंथन किया।

बैठक में निपुण प्लस ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप, इको क्लब, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, स्कूल बैंड व यूनिफॉर्म, ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण, नॉलेज शेयरिंग, एआरपी चयन, आईसीटी लैब एवं प्रशिक्षण सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक में विभिन्न विकास क्षेत्रों के एआरपी ने फील्ड स्तर की समस्याओं को सामने रखा, जिनके समाधान हेतु डायट प्राचार्य दरवेश कुमार ने

संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एसआरजी प्रशांत त्रिवेदी तथा जिला समन्वयक जितेंद्र कुमार ने निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी एआरपी को विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा।

डायट प्राचार्य व उप शिक्षा निदेशक ने निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से सभी विद्यालयों के बच्चों का शत-प्रतिशत आकलन कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि निपुण आकलन के समय विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति ही जनपद की रैंकिंग निर्धारित करेगी, इसलिए बच्चों की उपस्थिति पर विशेष जोर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि निपुण प्लस ऐप के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का नियमित मूल्यांकन कर शिक्षण रणनीति तय की जाए, ताकि सभी बच्चे निर्धारित दक्षताओं तक पहुंच सकें।

बैठक का संचालन नोडल अमित कुमार शर्मा ने किया।

इस अवसर पर डायट प्रवक्ता एवं विभिन्न कार्यक्रमों के नोडल अमित कुमार, स्वदेश कुमार, पुलकित शर्मा सहित एसआरजी, जिला समन्वयक और सभी ब्लॉकों के एआरपी उपस्थित रहे।

बीसलपुर मंडी में धान खरीद व्यवस्था पर उठे सवाल, ठण्ड में किसानों की बढ़ी परेशानियाँ

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर। कड़कड़ाती ठण्ड ने जहां किसानों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं सरकारी धान खरीद व्यवस्था में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोपों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बीसलपुर मंडी क्षेत्र में धान खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं।सूत्रों के अनुसार, कई क्रय केंद्रों पर धान की वास्तविक तौल किए बिना ही कागजों में खरीद दर्ज की जा रही है। फच्छ के कुछ केंद्रों पर किसानों से धान खरीदी के नाम पर अंगूठे लगवाकर राइस मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है। प्रतिदिन लाखों रुपये की अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है।किसानों का कहना है कि शासन-प्रशासन के सख्त निदेशों के

बावजूद क्रय केंद्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मंडी में टोकन व्यवस्था के नाम पर भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंडी सचिव ने "टोकन बदलो योजना" चला रखी है, जिसके अंतर्गत राइस मिलरों को प्राथमिकता देकर खुलेआम धान खरीद की व्यवस्था में हेराफेरी की जा रही है।स्थानीय किसानों ने मांग की है कि बीसलपुर मंडी की धान खरीद प्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। प्रशासनिक मौन ने इन शिकायतों को और गंभीर बना दिया है।

भाजपा नेता राकेश कर्रा ने की प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात

नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलकर संगठन मजबूती पर हुई चर्चा

(जीएनएस)।

बाराबंकी। जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश वर्मा कर्रा ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राकेश कर्रा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी। यह मुलाकात न सिर्फ औपचारिक थी, बल्कि बाराबंकी जनपद में संगठन को मजबूत बनाने, बूथ स्तर पर कार्यकताओं की सक्रियता बढ़ाने और आगामी चुनावों की रणनीति पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बातचीत भी रही। भाजपा नेता राकेश वर्मा कर्रा ने इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भगवान श्रीराम की एक सुंदर प्रतिमा भेंट की, जो अयोध्या की आस्था और भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। राकेश वर्मा कर्रा ने प्रदेश अध्यक्ष को बाराबंकी जिले में विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक स्थिति, कार्यकताओं की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों से अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकताओं से निरंतर संवाद बनाए रखने, जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और संगठनात्मक अनुशासन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। राकेश कर्रा ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी जमीन सं जुड़े हुए लोकप्रिय नेता है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और मजबूती के साथ जनसेवा एवं विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। वर्मा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी राकेश कर्रा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकताओं के सहयोग से भाजपा उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती के साथ जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी। राकेश वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि बाराबंकी में भाजपा कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी हित में कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे।

प्रमुख सचिव पी0 गुरूप्रसाद ने मेला क्षेत्र का भ्रमण कर माघ मेला-2026 के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों का लिया जायजा,

(जीएनएस)। प्रयागराज

सभी सम्बंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग श्री पी0 गुरूप्रसाद मंगलवार को मेलाधिकारी श्री ऋषिराज व नगर आयुक्त श्री सांई तेजा के साथ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर माघ मेला-2026 के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों का जायजा लिया तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सर्वप्रथम संगम नोज पहुंचकर वॉच टॉवर से मेला क्षेत्र का जायजा लिया तथा वॉच टॉवर से ही संगम नोज व सेक्टर-4 में बनाये जा रहे घाटों की प्रगति को भी देखा तथा मेलाधिकारी से सभी सेक्टरों की लोकेशन, नदी के वाटर लेवल एवं घाटों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। तत्पश्चात प्रमुख सचिव ने सेक्टर-4 में महावीर पुल के पास बड़े क्षेत्र में स्नान घाट बनाये जाने हेतु बढ़ाये जा रहे सकुर्लेटिंग एरिया के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता सिंचाई से मड पम्प के द्वारा बढ़ाये जा रहे सकुर्लेटिंग एरिया के कार्य के बारे में जानकारी ली और कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा, के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि कार्य तेजी के साथ चल रहा है और जल्द ही सकुर्लेटिंग एरिया को बढ़ाये जाने के कार्य को पूर्ण कर स्नान हेतु बड़े क्षेत्र में घाट तैयार कर लिया जायेगा, जिससे श्रद्धालुओं को प्रमुख स्नान पर्वों के समय कोई असुविधा नहीं होगी। तत्पश्चात प्रमुख सचिव ने साधु-संतो से बातचीत कर मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने भ्रमणकर चकर्ड प्लेट बिछाये जाने का कार्य व सड़क पर पानी छिड़काव, वाटर सप्लाई लाइन तथा साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को देखा तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर-6 में नए-नए बस रहे कैम्पों में जाकर पानी की सप्लाई को चलवाकर देखा तथा कैम्पवासियों से भी उन्हें वाटर कनेक्शन कब मिला, कोई परेशानी तो नहीं है, आदि के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता के द्वारा बताया गया कि सभी सेक्टरों में वाटर लाइन बिछायी जा चुकी है तथा सेक्टर-4 व 5 में अधिकांशतः सभी कनेक्शन हो चुके है तथा सेक्टर-6 में जैसे-जैसे कैम्पों की बाउंड्री हो रही है, प्रत्येक कैम्प में पानी की सप्लाई शुरू करा दी जा रही है और आवश्यकतानुसार प्वाइंट बढ़ाये जा रहे है। उन्होंने बताया कि 67 कैम्पों में आज कनेक्शन दे दिया गया है। प्रमुख सचिव ने कहा कि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, सभी को समय से आवश्कतानुसार स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। उन्होंने सेक्टर 1, 4, 5, 6 व सेक्टर 2 का क्रमशः भ्रमण कर की गयी तैयारियों का विधिवत निरीक्षण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान कल्पवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली व निरीक्षण कर जायजा भी लिया। उन्होंनें सेक्टर-6 में बनाये गये अग्निशमन केन्द्र का भी निरीक्षण किया।

प्रमुख सचिव ने माघ मेला के दृष्टिगत जल की स्वच्छता व निर्मलता को सुनिश्चित किए जाने हेतु नागवासुकी के पास जिओ ट्यूब के माध्यम से ड्रेनवाटर की प्यूरीफिकेशन के कार्य का निरीक्षण किया तथा प्रासेस फ्लो डायग्राम के माध्यम से जलशोधन की विस्तार से जानकारी ली तथा शोधन के पश्चात ही स्वच्छ जल ही गंगा जी में जाये, सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

इस अवसर पर विशेष सचिव श्री सत्य प्रकाश पटेल, मेलाधिकारी श्री ऋषिराज, नगर आयुक्त श्री सीलम सांई तेजा, सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण श्री अजीत सिंह, मुख्य अभियंता जल निगम नगरीय श्री संजय कुमार गौतम, अधीक्षण अभियंता श्री संजय कुमार रंजन, अधिशासी अभियंता श्री आशुतोष एवं अमितराज सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

डी.ई.एस.आई.जी.एन. (डिजाइन) फॉर बायो-ई3 चैलेंज के नवंबर, 2025 के 10 विजेता को नई दिल्ली स्थित आईसीजीईबी में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया

दस विजेता समाधानों के पास 3 महीने के अंदर बीआईआरएसी को एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विकल्प है, जिसके अंतर्गत उन्हें 'डिजाइन आइडिया' को 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' में बदलने के लिए 25 लाख रुपये तक का अनुसंधान, विकास और नवाचार अनुदान प्राप्त होगा

डिजाइन फॉर बायो-ई3 चैलेंजः युवाओं को अपने समय के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनानाः डिजाइन फॉर बायो-ई3 प्रतियोगिता के विजेताओं का अभिनंदन

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को बायो-ई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति को मंजूरी दी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई बायो-ई3 नीति जैव-विनिर्माण के माध्यम से अधिक न्यायसंगत और सतत भविष्य के निर्माण के लिए जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और डिजिटलीकरण के बीच समन्वय स्थापित करती है। बायो-ई3 नीति हरित, स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना करती है जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करेगी।

प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2025 को युवाओं की भागीदारी के आ'ान को दोहराते हुए , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने "अपने समय के महत्वपूर्ण मुद्दों

को हल करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना" विषय पर आधारित "डिजाइन फॉर बायो-ई3 चैलेंज" को दो श्रेणियों में शुभारंभ किया। श्रेणी 1, कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए खुली है और इसे मायगव के इनोवेट पोर्टल पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं, श्रेणी 2 सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है और इसे ब्रिक वेबसाइट पर आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाना, युवा नेतृत्व वाले बदलाव को बढ़ावा देना और भारत को सतत एवं आत्मनिर्भर जैव अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना है। डिजाइन फॉर बायो-ई3 चैलेंज सालों भर चलने वाली चुनौती है जो 1 अक्टूबर, 2026 तक हर महीने की पहली तारीख को शुरू होगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग , बिराक और ब्रिक संयुक्त रूप से डिजाइन फॉर बायो-ई3 चैलेंज का कार्यान्वयन कर रहे हैं। नवंबर 2025 के लिए प्रतियोगिता में 852 प्रस्ताव प्राप्त हुए। एक विशेषज्ञ समिति ने सभी प्रस्तावों की समीक्षा गोपनीय तरीके से की, अर्थात आवेदकों की पहचान और संबद्धता को समीक्षकों से छुपाया गया। नवंबर 2025 के लिए प्रतियोगिता की शीर्ष 10 विजेता टीमों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, बीआरआईसी के महानिदेशक और बीआईआरएसी के अध्यक्ष डॉ. राजेश एस. गोखले ने 30 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजित एक समारोह में नवंबर 2025 के लिए आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। बीआईआरएसी ने ग्रैंड चैलेंज इंडिया के माध्यम से 10 विजेता टीमों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। इन 10 विजेता समाधानों के पास 3 महीने के अंदर बीआईआरएसी को एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विकल्प है, जिसके अंतर्गत वे 'डिजाइन आइडिया' को 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' में बदलने के लिए 25 लाख रुपये तक के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव